MOST IMMEDATE
PARLIAMENTARY MATTER

No.-19-20/2021-M&T(Admn.)
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
(Mechanisation & Technology Division)

Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Dated : 10th October, 2022

OFFICE MEMORANDAM

Subject: 164th and 165th Reports of the Committee on Papers laid on the Table of Rajya Sabha

The undersigned is directed to refer to this Section's O.M. of even number dated 23rd September, 2022 on the subject mention above and to say that requisite information is still awaited from the Division.

2. You are requested to provide the latest status on the uploading of Review and Delay Statement on the websites of the respective SAICs, in response to the recommendation contained in the para no.2.57 to 2.59 urgently. The details of the review and delay statement have been uploaded on the SAIC websites. If the review and delay statement are not uploaded on the websites, please upload the review and delay statement on your website and inform the Ministry. The information may also be mailed at E-mail : raj.kumar36@nic.in

ENT 1874 A/C
DATE 26.10.22.

Encl : As above.

10/10/2022
(Raj Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23381557

MD
Dy M (Acct)

3230
MD 20/10/22.

To,
All Managing Director of
State Agro Industries Corporations Limited

1. Andhra Pradesh-Vijayawada
2. Bihar-Patna
3. Haryana-Chandigarh
4. Himachal Pradesh-Shimla
5. Jammu & Kashmir-Srinagar
6. Kerala-Thiruvanthapuram
7. Madhya Pradesh-Bhopal
8. Maharashtra-Mumbai
9. Odisha-Bhubaneshwar
10. Punjab-Chandigarh

M.P. SAIDC. HO, BHOPAL
Date of Receipt 20-10-2022
Received From ...
Corr. No. ...
Inward No. 2729 Date 20-10-22
Signature

पर रखे जाने वाले

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

वर्ष 2017-18 के लिए मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण ।

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन एक प्रतिष्ठान है । भारत सरकार की निगम में लगभग 36.41 प्रतिशत की हिस्सेदारी है ।

2. कम्पनी अधिनियम, 213 की धारा 394(1) के प्रावधानों के अनुसार, जहां केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी की एक सदस्य है, केन्द्रीय सरकार कम्पनी की कार्य प्रणाली और मामलों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट :

(क) इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीनों के भीतर, जिससे पहले धारा 143 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, तैयार करवाएगी; तथा

(ख) इस तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इस पर की गई टिप्पणियों अथवा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएगी ।

3. इसके अलावा, राज्य सभा के पटल पर रखे गए ' कागजातों से संबंधित समिति ' की प्रथम रिपोर्ट के पैरा 26 में की गई सिफारिशों के अनुसार, निगम की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा-परीक्षित खातों की प्रतियां को, लेखों के बन्द होने के 9 महीनों के भीतर लेखा परीक्षकों और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट/समीक्षा टिप्पणियों सहित, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना अनिवार्य है ।

4. विलंब के कारण हैं:

i. गत वर्षों के लेखों को अंतिम होने पर विलंब का प्रभाव वर्ष 2017-18 के लेखों पर पड़ा है जब तक पूर्व वर्ष के लेखे वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं किये जाते तब तक सावधिक अंकेक्षण द्वारा अगले वर्ष के लेखों को सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

ii. शाखाओं में लेखा कर्मचारियों की पदस्थापना रिक्त होने के कारण लेखों का अंतिमीकरण कार्य प्रभावित हुआ है।

5. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लंबित वार्षिक रिपोर्टो एवं लेखा परीक्षित खातों की प्रस्तुति में तेजी लाने के लिए निगम और राज्य सरकार के साथ मामले को उठाता रहा है । इस तरह से सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2017-18के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित खाते भेजे जाने के लिए निगम सक्षम है ।

6. वर्ष 2017-18के लिए मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम के वार्षिक लेखों को अंतिम रुप देने में हुए विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	कार्य	तिथि
1	वैधानिक अंकक्षेकों की नियुक्ति	01.08.2017
2	शाखा स्तर पर लेखों का संकलन	31.12.2018
3	मुख्यालय स्तर पर लेखों का संकलन	31. 01.2019
4	अंकक्षेकों द्वारा अंकेक्षण पूर्ण किया गया	19.08.2019
5	संचालक मंडल से अनुमोदन	27.08.2019
6	सांविधिक अंकक्षेक द्वारा लेखों पर सत्यापन	24.10.2019
7	लेखों को पूरक अंकेक्षण हेतु महालेखाकार ग्वालियर को प्रेषित	26.10.2019
8	पूरक अंकेक्षणकार्य पूर्ण करने की तिथि	11.12.2019
9	नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अंतिम टिप्पणियाँ प्राप्त	10.01.2020
10	वार्षिक साधारण सभा द्वारा अंगीकृत	20.07.2020
1	मुद्रित प्रतियां भेजने की तिथि	18.12.2020
12	वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त	22.12.2020

7. अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में विलंब हुआ ।

******

AUTHENTICATED

PARSHOTTAM RUPALA
Minister of State
Ministry of Agriculture & Farmers Welfa
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi

<u>STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE ANNUAL REPORT & AUDITED ACCOUNTS OF MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 2017-18 ON THE TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA.</u>

The Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited is an undertaking under the direct control of the State Government of Madhya Pradesh. The Government of India has a shareholding of about 36.41.% in the Corporation.

2. As per provisions contained under Section 394(1) of the Companies Act. 2013. where the Central Government is a member of a Government Company, the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of the Company to be:

(a) prepared within three months of its annual general meeting before which the audit report is placed under sub-section (6) of Section 143: and.

(b) as soon as may be after such preparation, laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to the audit report, made by the Comptroller and Auditor General of India.

3. Further, in accordance with the recommendations contained in para 26 of the 1st Report of "Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha", copies of the Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation are to be placed on the Table of both the Houses of Parliament together with report/review, comments of auditors and Comptroller and Auditor General within 9 months of closure of the accounts.

4. <u>Reasons for Delay are:</u>

i. The delay in finalization of accounts of previous year affected the accounts of 2017-18. Statutory Auditor does not certify the Account of year 2017-18, unless the accounts of previous year adopted in Annual General Meeting.

ii. In some Branches non posting of Accountants delayed the process of finalization of accounts.

5. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare have been vigorously pursuing the matter with the Corporation as well as with the State Government to expedite submission of pending Annual Report and Audited Accounts of the Corporation for the year 2017-18 to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for laying on the Table of the House.

6. The reasons for finalization of Annual Accounts of the Madhya Pradesh Agro Industries Development Corporation Limited for the year 2017-18 are as under.

	Task	Date with Period
1.	Appointment of Statutory Auditor	01.08.2017
2.	Completion of Accounts at Branch level	31.12.2018
3.	Completion of Accounts at Head Office level	31. 01.2019
4.	Completion of Audit by Statutory Auditor	19.08.2019
5.	Approval of Accounts by Board	27.08.2019
6.	Certification of Statutory Auditors	24.10.2019
7.	Accounts sent to AGMP, Gwalior for appointment of supplementary audit	26.10.2019
8.	Completion of A.G. Audit	11.12.2019
9.	Receipt of final comments from AGMP, Gwalior	10.01.2020
10.	Date of Annual General Meeting	20.07.2020
11.	Submission of Printed Copies	18.12.2020
12.	Annual Report received in this Ministry	22.12.2020

7. Hence, there has been a delay in laying the report on the table of the Houses.

******

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

वर्ष 2017-18 हेतु मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलाप की समीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की साम्य हिस्सेदारी से एक सरकारी कंपनी के रूप में वर्ष 1967 में निगमित किया गया था । निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी 5.00 करोड़ रू0 है । वर्ष 2017-18 के अंत में निगम की प्रदत्त पूंजी 3.29 करोड़ रूपये थी । प्रदत्त पूंजी मे केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 1.2 करोड़ रूपये अर्थात निगम की कुल प्रदत्त पूंजी का लगभग 36.41 प्रतिशत है ।

2. **उद्देश्य:**

निगम के मुख्य उद्देश्य परियोजना स्कीमों, उद्योगों, व्यवसाय तथा अन्य कार्यकलापों को बढ़ावा देना, विकसित करना, स्थापित करना, निष्पादित करना, प्रचालित करना और अन्यथा चलाना जो कि कम्पनी के मत के अनुसार संभवत: निम्न में योगदान करेंगे:-

(क) कृषि उत्पादन को तेज करना और इसमें वृद्धि करना;
(ख) पूरक और अनुपूरक खाद्य के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करना;
(ग) मध्य प्रदेश राज्य में खाद्य की आपूर्ति चाहे वह मुख्य हो, सहायक अनुपूरक हो या स्थानापन्न हो, की उपलब्धता में वृद्धि करना; और
(घ) मध्य प्रदेश के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान करना;

3. **कार्यकलाप और निष्पादन:**

निगम के मुख्य कार्यकलापों में ट्रैक्टरों और संबद्ध पुर्जों, पम्पसेटों, स्प्रिंकलर, थ्रेसर, पीपी उपकरणों, ड्रिप सिंचाई, टायर एवं ट्यूब, बैटरी, उर्वरक, नाशीजीवमार, कस्टम हायरिंग एवं कृषि उपकरण आदि की बिक्री एवं सेवा शामिल है । निगम की कुल बिक्री एवं सेवा संबंधी कारोबार वर्ष 2016-17 के दौरान 1363.28 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 985.99 करोड़ रूपये था जो पिछले वर्ष के कार्य परिणाम की तुलना में 27.67% की कमी दर्शाता है।

4. **लाभ और हानि की स्थिति:**

निगम को वर्ष 2016-17 के दौरान 5269.82 लाख रूपये की लाभ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 3576.15 लाख रूपये का लाभ हुआ।

Papers to be laid on the Table
of the Lok Sabha/Rajya Sabha

AUTHENTICATED

25/1/21

PARSHOTTAM RUPALA
Minister of State
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi

REVIEW OF ACTIVITIES OF THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 2017-18.

The Madhya Pradesh State Agro Industries Corporation Limited was incorporated in the year 1967 under the Companies Act, 1956 as a Government Company with equity participation of the Central Government and the State Government of Madhya Pradesh. The authorized share capital of the Corporation is Rs. 5.00 crores. The paid-up capital of the Corporation is Rs. 3.29 crores at the end of 2017-18. The Central Government's share in the paid-up capital is Rs. 1.2 crores which is about 36.41% of the total paid up capital of the corporation.

2. OBJECTIVES :

The main objective of the corporation is to promote, develop, establish, execute, operate and carry out projects, schemes, industries, business and other activities which in the opinion of the company are likely to:

A. Accelerate and increase agricultural production;
B. Contribute to the production of subsidiary and supplementary food;
C. Increase the availability of supplies of food whether principal, ancillary supplementary or substitute in the State of Madhya Pradesh; and
D. Contribute towards the development of agro industries in Madhya Pradesh.

3. ACTIVITIES AND PERFORMANCE:

The main activities of the Corporation include sales and service of Tractors and accessories, Pump-sets, Sprinkler, Thresher, PP equipment, Drip Irrigation, Tyres and Tubes, Battery, Fertilizer, Pesticides, Custom Hiring and Agricultural Implements etc. The sales and Services turnover of the Corporation during 2017-18 is Rs. 985.99 crore, as compared to Rs. 1363.28 crore in 2016-17 depicting an decreasing trend by 27.67% over last year's working result.

4. PROFIT AND LOSS POSITION:

During 2017-18, the Corporation has generated a profit of Rs. 3576.15 lakhs as against a profit of Rs. 5269.82 lakhs earned during the year 2016-17.

******